प्रसार भारती
भारतीय प्रसारण निगम
आकाशवाणी केन्द्र शिमला

31.01.2026 / प्रादेशिक समाचार / रितेश कपूर / 9:20बजे

'आज के मुख्य समाचार''

- वित्त् मंत्री निर्मला सीतारामन कल पहली फरवरी को लोकसभा में वर्ष 2026–27 का केन्द्रीय बजट करेंगी प्रस्तुत।
- कैबिनेट मंत्री यादवेंद्र गोमा ने उपायुक्त मंडी के खिलाफ विधानसभा अध्यक्ष को सौंपा विशेषाधिकार हनन का नोटिस।
- प्रदेश की 3 हजार 5 सौ 77 पंचायतों का पांच साल का कार्यकाल आज होगा समाप्त।
- अर्की विधानसभा क्षेत्र में 30 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित होगा दूध प्रसंस्करण संयंत्र ।

केन्द्रीय बजट

केन्द्रीय वित्त् मंत्री निर्मला सीतारामन कल पहली फरवरी को लोकसभा में वर्ष 2026–27 का केन्द्रीय बजट प्रस्तुत करेंगी। लोकसभा के बाद बजट की प्रति राज्यसभा के पटल पर रखी जाएगी। वर्ष 2019 में वित्त मंत्री का कार्यभार सम्भालने के बाद यह निर्मला सीतारामन का लगातार नौवां बजट है। संसद में बजट भाषण सम्पन्नं होने के बाद बजट की प्रति मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगी। इस बीच देश के विभिन्न हिस्सों से आए महाविद्यालयों के लगभग तीस विद्यार्थियों को कल लोकसभा गैलरी से केंद्रीय बजट का सीधा प्रसारण देखने का अवसर मिलेगा। वित्त मंत्रालय ने वक्तव्य में कहा है कि इससे विद्यार्थियों को वर्ष की सबसे महत्वपूर्ण संसदीय कार्यवाही देखने का अवसर मिलेगा। ये विद्यार्थी भारत के विभिन्न राज्यों से वाणिज्य, अर्थशास्त्र, चिकित्सा और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों सहित विभिन्न शैक्षणिक विषयों से संबंधित हैं। विद्यार्थी कर्तव्य भवन–1 स्थित वित्त मंत्रालय का दौरा भी करेंगे। इससे उन्हें मंत्रालय के कामकाज, नीति निर्माण प्रक्रियाओं और राष्ट्र निर्माण में संस्थानों की भूमिका को समझने का अवसर प्राप्तय होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन शाम को इन विद्यार्थियों के साथ संवाद करेंगी और बजट की प्रमुख प्राथमिकताओं, देश के भविष्य के लिए इसके दृष्टिकोण और युवाओं पर इसके प्रभावों पर चर्चा करेंगी।

विशेषाधिकार हनन

मंडी में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान निर्धारित सरकारी प्रोटोकॉल का पालन न होने पर आयुष, युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री यादविंद्र गोमा ने उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन के खिलाफ विधानसभा

अध्यक्ष को विशेषाधिकार हनन का नोटिस सौंपा है। यह नोटिस हिमाचल प्रदेश विधानसभा की कार्यविधि एवं कार्य संचालन नियमावली के अध्याय–12 के नियम–75 के तहत प्रस्तुत किया गया है। अपने नोटिस में यादविंद्र गोमा ने उल्लेख किया है कि वह 25 जनवरी को पूर्ण राज्यत्व दिवस समारोह में भाग लेने के लिए मंडी पहुंचे थे, लेकिन उनके आगमन के समय न तो उपायुक्त मंडी उपस्थित थे और न ही प्रशासन की ओर से किसी प्रकार की आधिकारिक सूचना या आवश्यक व्यवस्थाएं की गई थीं।

26 जनवरी का कार्यक्रम पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। माननीय मुख्यमंत्री ने मुझे मंडी जिला में झंडा फहराने के लिए नियुक्त किया गया था। वहां पर जब मैं पहुंचा तो सब लोग, सभी कार्यकर्ता, अधिकारी, एसपी, एडीसी, सारा स्टाफ जबकि उपायुक्त मंडी वहां पर मौजूद नहीं थे और उन्होंने मुझे इस विषय में कोई भी मैसिज कनवे नहीं किया था मैने अपने कुलिग से भी इस विषय पर  बातचीत की और परिणाम यह निकला की उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया जाए ताकि आने वाले समय में किसी के साथ भी ऐसा न हो।

अनुराग ठाकुर

पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग ठाकुर ने विकसित भारत गारंटी फॉर रोज़गार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण योजना को मोदी सरकार का दूरदर्शी व परिवर्तनकारी विज़न बताया है। उन्होंने कल जसवां–परागपुर विधानसभा क्षेत्र के जंडौर और चिंतपूर्णी में आयोजित जनसभाओं को संबोधित करते हुए ये बात कही। अनुराग ठाकुर ने कहा कि ये पहल मज़दूर हित ग्रामीण रोज़गार व अर्थव्यवस्था को सशक्त करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने मनरेगा में व्यापक सुधार करते हुए उसे विकसित भारत जी राम जी योजना के रूप में आगे बढ़ाने का काम किया है और इसके तहत अबएक सौ 25 दिनों का रोज़गार सुनिश्चित किया जाएगा।

*100 दिन दिहाड़ी नहीं 125 दिनों का रोजगार मिलेगा कांगेस से ज्यादा रोजगार जीरामजी के तहत हमारी सरकार ने गारंटी दी है और जब खेतीबाड़ी के दिनों में फसला का होगा तो उन जीरामजी को 60 दिनों बंद किया जाएगा ताकि मजदूर दिहाड़ी भी लगाएं या अपना खेत हो तो अपना कार्य भी करें।*

चंद्र कुमार

कृषि व पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने कहा है कि प्रदेश सरकार विकास को जन सरोकारों से जोड़कर आगे बढ़ रही है और समाज से हर वर्ग के उत्थान के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। ये बात कल उन्होंने नगरोटा–सूरियां क्षेत्र की सुकनाड़ा पंचायत में निर्मित सामुदायिक भवन और राजकीय माध्यमिक विद्यालय सुकनाड़ा के अतिरिक्त भवन के उद्घाटन अवसर पर कही।

पंचायत

प्रदेश की 3 हजार 5 सौ 77 पंचायतों का पांच साल का कार्यकाल आज पूरा हो रहा है। इसके बाद आज आधी रात के बाद प्रदेश की सभी पंचायतें अपने आप ही भंग हो जाएगी। प्रदेश में पहली बार फरवरी से पंचायतों में निर्वाचित प्रतिनिधियों की जगह दूसरी वैकल्पिक व्यव्सथा लागू होगी। लोकतंत्र की सबसे निचली और सबसे अहम इकाई सरकार के अगले आदेशों के मुताबिक चलाई जाएगी। इसको लेकर पंचायती राज विभाग ने सरकार को मामला भेजा है।

संजय अवस्थी

अर्की विधानसभा क्षेत्र में आने वाले समय में लगभग 30 करोड़ रुपए की लागत से दूध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया जाएगा। इससे क्षेत्र में लोगों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। यह बात अर्की के विधायक संजय अवस्थी ने कल अर्की विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत दसेरन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कही। इस अवसर पर उन्होंने यहां पर 12 लाख से निर्मित क्षेत्रीय कानूनगो कार्यालय भराड़ीघाट का लोकार्पण किया।

टीबी मुक्त भारत अभियान

प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान – क्षय मित्र के माध्यम से वर्ष 2025 तक देश को क्षय रोग से मुक्त करवाने का लक्ष्य अब हासिल होता नजर आ रहा है । राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत चलाया जा रहा यह कार्यक्रम, भारत की प्रमुख केंद्र प्रायोजित पहल है जो देश भर में टीबी की बीमारी को समाप्त करने के उद्देश्य से चलाई जा रही है।

*टीबी मुक्त ऊना के संकल्प को साकार करने के लिए जिला स्वास्थ्य विभाग ने इस वर्ष ऊना की सभी पंचायतों को क्षय रोग मुक्त घोषित करने का लक्ष्य रखा है। आधुनिक तकनीक, सुदृढ़ योजनाओं और व्यापक जन–भागीदारी के सहारे यह अभियान अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है। जहां एक ओर स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन और स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से गांव–स्तर तक जागरूकता सुनिश्चित की जा रही है, वहीं घर–घर जाकर स्वास्थ्य कर्मी टीबी के संभावित मरीजों की •–रे और बलगम जांच करने के उपरांत रोगियों के मुफ़्त इलाज की व्यवस्था करवा रहे हैं । अभियान के माध्यम से गत वर्ष लगभग 31 हजार संभावित रोगियों की जांच हो चुकी है, जिनमें से 530 क्षय रोगियों की पुष्टि हुई है। शीघ्र पहचान, समयबद्ध उपचार और पोषण सहायता की मदद से ऊना जिला, क्षय रोग मुक्ति के लक्ष्य की ओर अग्रसर है ।*

कुलदीप सिंह पठानिया

विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने भटियात विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत मेल में बनने वाली सड़क का विधिवत भूमि पूजन किया। लोक निर्माण विभाग द्वारा 41 लाख रुपए की लागत से बनाई जा रही 1 दशमलव 25 किलो मीटर लंबी इस सड़क के बनने से ग्राम पंचायत मेल की लगभग 5 सौ की आवादी लाभांवित होगी। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण में भटियात विधानसभा क्षेत्र की 12 ग्रामीण सड़कों को केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। 103 करोड 53 लाख रुपए की लागत से बनने वाली इन सड़कों की कुल लंबाई 67 दशमलव 22 किलोमीटर है। उन्होंने बताया कि पीएमजीएसवाई–4 के तहत जिला चंबा में लगभग 500 करोड़ रूपए खर्च किए जा रहे हैं। कुलदीप सिंह पठानिया ने जानकारी दी कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने पांच बड़े राष्ट्रीय राजमार्गों के प्रस्ताव स्वीकृति के लिए केंद्र सरकार को भेजे हैं। जिसमें प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग द्रमण – सिंहुता–लाहडू–जोत– चम्बा भी शामिल है।

अब सुर्खियां समाचार पत्रों से.....

आज समाचार पत्रों ने अलग–अलग खबरों को प्रमुखता दी हैं.....

अमर उजाला का शीर्षक है– पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू, शिमला समेत कई जिलों में मतदाता सूची जारी। पंजाब केसरी लिखता है–आज प्रधानगिरी का अंतिम दिन, कल 3 हजार 5 सौ 77 पंचायतों का कार्यकाल होगा पूरा

मौसम पर दैनिक भास्कर की सुर्खी है–धूप खिली तो पीडब्लयूडी ने 24 घंटे में 1 सौ 70 सड़कें खोलीं, 4 सौ 82 सड़कें अभी बंद– सुबह शाम ठंड बरकरार, आज से 3 दिन फिर बर्फबारी, बारिश के आसार।

''अंत में मुख्य समाचार'' एक बार फिर

- वित्त् मंत्री निर्मला सीतारामन कल पहली फरवरी को लोकसभा में वर्ष 2026–27 का केन्द्रीय बजट करेंगी प्रस्तुत।
- कैबिनेट मंत्री यादवेंद्र गोमा ने उपायुक्त मंडी के खिलाफ विधानसभा अध्यक्ष को सौंपा विशेषाधिकार हनन का नोटिस।
- प्रदेश की 3 हजार 5 सौ 77 पंचायतों का पांच साल का कार्यकाल आज होगा समाप्त।
- अर्की विधानसभा क्षेत्र में 30 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित होगा दूध प्रसंस्करण संयंत्र ।